फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 343 प्रभात जयपुर, मंगलवार 15 जुलाई, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

epaper.rashtradoot.com

Super Drink Or Soup- As You Wish

Can a tangy, spicy soup help you shed a few pounds? The answer might surprise you. Yes!!

Black Holes Are Weird

Iran Mall: A Persian Heritage with Modern Grandeur

Persian bazaar recreated inside, not a commercial gimmick, but a true homage to Iran's centuries-old market culture

लगभग सभी बड़ी एयर लाइन्स अब अपने बोइंग हवाई जहाजों की फ्यूल सप्लाई का पुनः निरीक्षण कर रही हैं

जैसा की विदित ही है, अहमदाबाद से लन्दन फ्लाइट का फ्यूल सप्लाई सिस्टम स्विच ऑफ हो गया था, फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ सैकण्ड में ही क्रैश हो गई थी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जुलाई। अब बोइंग विमानों में ईंधन नियंत्रण तंत्र (फ्यूल कंट्रोल मेकैनिज़्म) के संचालन को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है।

दुनियाभर की एयरलाइंस अब बोइंग विमानों में ईंधन नियंत्रण स्विचों की कार्यप्रणाली की दोबारा जांच कर रही हैं, खासकर उन रिपोर्ट्स के बाद जिनमें उड़ान के दौरान इंजन को अचानक ईंधन की आपूर्ति बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। कई प्रमुख एयरलाइनों ने इन फ्यूल सप्लाई स्विचों की कार्य प्रणाली की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

एयर इंडिया ने भी अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्देश पर अपने सभी बड़े बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच और उसके लॉकिंग सिस्टम की जांच शुरू की है।

- **अमेरिका की फैडरल एविएशन अथॉरिटी, जो हवाई जहाजों की सेफ्टी व ऑपरेशन्स पर कड़ी नज़र रखती है, ने दिसम्बर 2018 में अपनी रिपोर्ट में आगाह किया था, बोइंग हवाई जहाजों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के काम-काज का बारीकी से निरीक्षण करने की आवश्यकता है।**
- **बोइंग कम्पनी सभी तरह के हवाई जहाजों में, ऐसे फ्यूल कंट्रोल स्विच ही काम में लेती है।**
- **बोइंग कम्पनी के कई वाइड बॉडी लॉंग रेंज हवाई जहाज, जैसे बोइंग 747 और बोइंग 787 तथा बोइंग 777 ड्रीम लाइनर तथा शॉर्ट रेंज के हवाई जहाज 737 में भी ऐसे फ्यूल कंट्रोल स्विच लगे हैं।**
- **बोइंग कम्पनी के ये हवाई जहाज, किसी भी बड़ी एयर लाइन्स के ''वर्क हॉर्स'' (सबसे अधिक काम में आने वाले) हवाई जहाज हैं।**

अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, जिसके चलते विमान कुछ ही सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच में सामने आया है कि फ्यूल सप्लाई स्विच में लॉकिंग मैकेनिज़्म मौजूद था, लेकिन वह संभवतः काम नहीं कर पाया।

भारतीय विमान दुर्घटना जांच संस्था ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि पायलटों के बीच फ्यूल सप्लाई स्विच को बंद करने को लेकर बातचीत हुई थी।

हालांकि दुर्घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा क्योंकि जांच में विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना होगा, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष से संभावित कारणों की भयावह झलक मिलती है।

ऐसी भी सूचना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की फैडरल एविएशन अथॉरिटी (एफएए) ने दिसंबर 2018

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के.आर. श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नौ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों से संबंधित आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें चार मुख्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण शामिल है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को मद्रास उच्च न्यायालय भेजा गया है। वहीं, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य

- **के.आर. श्रीराम, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, की जगह राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव लेंगे।**

न्यायाधीश के. आर. श्रीराम को राजस्थान स्थानांतरित किया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट से जस्टिस चन्द्रशेखर को बॉम्बे हाईकोर्ट और जस्टिस अरुण मोंगा को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया है। जज संजीव प्रकाश को पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट से वापस राजस्थान भेजा गया है।

त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को तेलंगाना उच्च न्यायालय भेजा गया है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अब शीघ्र ही सौ का आंकड़ा पार करेगी राज्यसभा में

अभी भाजपा के 99 सांसद हैं, राज्यसभा में और हाल ही में भाजपा ने चार सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है, अगर छह महीने में एक भी मनोनीत सदस्य भाजपा जॉइन कर लेता है तो भाजपा के सौ सदस्य हो जायेंगे राज्यसभा में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किए जाने के साथ ही यह संभावना बन गई है कि पार्टी, जिसके इस समय राज्यसभा में 99 सदस्य हैं, निकट भविष्य में 100 का आंकड़ा पार कर सकती है।

यह स्थिति तब बनेगी, जब इन चार में से कोई एक नामित सदस्य भी आगामी छह महीनों में भाजपा में शामिल हो जाए।

दो सौ पैंतालीस सदस्यों वाली राज्यसभा में, वर्तमान में एनडीए के पास 121 सीटें हैं, और वह तीन में से कम से कम एक निर्दलीय सदस्य और बहुसंख्यक मनोनीत सदस्यों के समर्थन पर भी निर्भर है। वर्तमान में, नामित सदस्यों में से दो - गुलाम अली और सतनाम सिंह संधू - भाजपा के 99 सदस्यों में शामिल हैं।

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक सप्ताह पहले सरकार ने नामित

- **चार मनोनीत सदस्यों में पहले तो हैं पूर्व विदेश सचिव हर्ष वर्द्धन सांखला, जिन्होंने 2023 में भारत में ''ग्रुप ऑफ ट्वैन्टी'' का शिखर सम्मेलन आयोजित किया था।**
- **उज्जवल निकम, दूसरे सदस्य हैं जो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं। उन्होंने 26/11 के आतंकवादी अटैक के मुख्य अपराधियों को सरकारी वकील की हैसियत से न्यायालय में सजा दिलवाई थी।**
- **तीसरे मनोनीत सदस्य, केरल के सदानन्द मास्टर हैं, जिनके दोनों पैर काट दिये थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने।**
- **चौथी मनोनीत सदस्य हैं, दिल्ली निवासी इतिहासकार मीनाक्षी जैन।**

श्रेणी की चार खाली सीटों को भर दिया है। जिन लोगों को नामित किया गया है, वे हैं: पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, केरल के भाजपा नेता सी. सदानंद मास्टर तथा दिल्ली निवासी इतिहासकार मीनाक्षी जैन।

श्रृंगला को 2023 में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक के रूप में उनके योगदान के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शेखर गुप्ता की वैबसाइट व संघ उन्मुख पत्रिका ऑर्गनाइज़र ने आशंका जताई

इन दोनों का कहना है, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखण्ड में संघ के कार्यकर्ता निराश हैं

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) के स्वयंसेवकों का अपेक्षित सहयोग शायद न मिल पाए। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भाजपा के चुनावी प्रचार से दूर हो रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रुप से असंतोष व्यक्त किया है।

'द प्रिन्ट' की एक हालिया अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आरएसएस के भीतर व्यापक असंतोष होने की बात सामने आई है।

स्वयंसेवक भाजपा सरकार द्वारा ठगे गये से महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की है - जैसे कि नौकरी से बर्खास्तगी, बैंक ऋणों में कठिनाई और एफआईआर दर्ज न होना आदि इन कारणों से अनेक स्वयंसेवकों ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूरी बना ली

- **इन दोनों सूत्रों का मानना है, यह भी सम्भावना है कि कार्यकर्ता घर बैठ जायें।**
- **भाजपा को इन कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले साथ लेने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि इन लोगों की मुख्य शिकायत है, कि पार्टी ने उनसे सलाह मशविरा नहीं किया, उम्मीदवारों के चयन व चुनाव के अन्य मुद्दों पर।**

है। हालांकि वे कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन मौन प्रतिरोध के रूप में, प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ''ऑर्गनाइज़र'' ने भी इस बात को कई बार उजागर किया है कि

''भाजपा ने न तो उम्मीदवार चयन में और न ही चुनाव प्रचार की योजना में आर एस एस के स्वयंसेवकों से सलाह ली।'' भाजपा के इस व्यवहार ने पुराने एवं समर्पित आरएसएस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया है। बहुत से अनुभवी स्वयंसेवकों से तो प्रचार में सहयोग तक नहीं मांगा गया।

भाजपा को इसका सीधा असर अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में अनेकानेक स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर के चुनाव प्रचार से चुपचाप दूरी बना ली है। उनका कहना है कि टिकट वितरण और रणनीति में उन्हें दरकिनार किया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो राज्यपाल और 1 उपराज्यपाल की नियुक्ति

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को गोवा और हरियाणा के दो नए राज्यपालों तथा लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति की।

तेलुगु देशम पार्टी के नेता पुसापाटी अशोक राजू (74), जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नागर विमानन

- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को अशोक राजू को गोवा का और अशीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया।**

राज्यमंत्री थे, को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, भाजपा के नेता तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जो हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में हार गए थे, को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष मोदी सरकार को पूरी तरह घेरने के प्रयास में है मानसून सत्र में

विपक्ष के घोषित मुद्दे हैं, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर तथा अचानक घोषित युद्ध विराम और वह भी, चर्चाओं के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 14 जुलाई।

नई दिल्ली, 14 जुलाई। नरेन्द्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद की न्यूनतम बैठकों का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे संवैधानिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों के बीच गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रवृत्ति विधायी निरीक्षण से बचने की जानबूझ कर की गई कोशिश को दर्शाती है। सरकार द्वारा विधायी निरीक्षण से बचने का प्रयास किया गया है, खासकर 2024 के आम चुनावों के बाद विपक्ष की मजबूत स्थिति को देखते हुए।

2019 में 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की तुलना वर्तमान 18वीं लोकसभा से करें तो अंतर स्पष्ट है। जहां 17वीं लोकसभा का मानसून सत्र 37 दिन चला और इसमें 16 विधेयक पारित हुए, जिनमें जम्मू और कश्मीर में

- **सुप्रीम कोर्ट की, चुनाव आयोग के काम काज पर की गई टिप्पणी ने भी विपक्ष के हौसले और ऊंचे कर दिये, सरकार को घेरने के लिए।**

अनुच्छेद 370 के निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय भी शामिल था, वहीं अधिकांश विधेयक बिना किसी सार्थक बहस या विपक्षी परामर्श के पारित कर दिए गए थे।

इसके विपरीत, विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान लोकसभा के पहले 12 महीनों में संसद की बैठकों के दिन और भी कम हो गए हैं, जो संसद की उत्पादकता में एक चिंताजनक गिरावट को दर्शाता है।

विश्लेषक विधायी समय की इस कमी को सीधे तौर पर मोदी सरकार की कमजोर राजनीतिक स्थिति से जोड़ते हैं। अब, भाजपा को तेलुगू देशम पार्टी जैसे गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह अधिक एकजुट और आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है।

इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत को देखते हुए राजनीतिक टिप्पणीकार एक पैटर्न देख रहे हैं: जैसे-जैसे विपक्ष की ताकत बढ़ रही है, मोदी सरकार संसद की बैठकों की संख्या घटा रही है ताकि सार्वजनिक मुद्दों पर बहस को सीमित किया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की संसद में उपस्थिति में भी उल्लेखनीय कमी आई है। हाल ही में पहलगाम घटना पर महत्वपूर्ण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने पर विपक्षी नेताओं ने मोदी की आलोचना की, विशेषकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति दांव पर लगी हुई थी। इस संदर्भ में, आगामी मानसून सत्र, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, मोदी सरकार के लिए एक बड़े विधायी परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी दल कई मोर्चों पर सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं: पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अचानक सीज़फायर की घोषणा, जो कथित तौर पर अमेरिकी दबाव में, संसद से परामर्श किए बिना, किया। घरेलू मुद्दे जैसे मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, कृषि संकट, जाति जनगणना डेटा प्रबंधन, और चुनावी सूची में संशोधन, भी एजेंडा में हैं।

सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गये हैं, जिन्होंने आग में घी का काम किया है। शीर्ष उद्योगपतियों से जुड़ी क्रोनी कैपिटलिज़्म पर ताजा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. पेपर लीक में हाईकोर्ट ने एस.आई.टी. चेयरमैन को बुलाया

जयपुर, 14 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी चेयरमैन को मंगलवार को उपस्थित होने के लिए कहा है। अदालत ने एसआईटी चेयरमैन का पक्ष जानने की मंशा जताई है कि चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के दौरान

- **अदालत उनसे जानना चाहती है कि चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के दौरान लिये गये टैस्ट को लेकर क्या कार्यवाही हुई।**

लिए गए टैस्ट को लेकर क्या कार्रवाई हुई थी। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को दिया।

सुनवाई के दौरान, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान ग्लोबल मैडिकल टूरिज़्म हब बनेगा

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, नगरीय विकास पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए

जयपुर, 14 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने, मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढ ांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी।

- **मंत्रिमंडल ने ''हील इन राजस्थान नीति-2025'' के प्रारूप का अनुमोदन किया। यह नीति राज्य को भरोसेमंद मैडिकल वैल्यू ट्रेवल डैस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी।**
- **प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए नवीन टाऊनशिप पॉलिसी 2024 लाई जायेगी।**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने बताया कि हील इन राजस्थान नीति-2025 से मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धितयों, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी।

गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी आज मंत्रिमंडल द्वारा किया गया।

उपमुख्मयंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार संवर्ग में कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में आई.सी.ए.आर. के स्थान पर, यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत, सदस्यों के 3 नवीन पद सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे।